



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5100]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940

No. 5100]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSAH 7, 1940

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6354(अ).—यतः केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना-2021 के संबंध में जिन कठिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.08.2014 के का.आ. 2177(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पैंतालीस दिन (45) के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

पैरा/क्र.सं.	दिल्ली मुख्य योजना-2021	
	दिल्ली मुख्य योजना में विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन
अध्याय-7.0 उद्योग		
1.	7.4 घरेलू/सेवा उद्योग	
	ii) औद्योगिक इकाइयों की अनुमति केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनंतिम	उप-पैरा (ii) को हटा दिया जाए; और उप-पैरा (iii) से (vi) तक दोबारा (ii) से (v) तक के रूप में नंबर डाला जाए।

	पंजीकरण के बाद ही दी जाए।	
2.	7.8 औद्योगिक उपयोग जॉन-मार्गनिर्देश	
	i) विकसित किए जाने वाले नए औद्योगिक क्षेत्रों का भूखंडीय विकास पृथक औद्योगिक इकाइयों के लिए किया जा सकता है।	i) विकसित किए जाने वाले नए औद्योगिक क्षेत्रों का भूखंडीय विकास पृथक औद्योगिक इकाइयों के लिए किया जा सकता है।

[फा.सं. के-12011/5/2017-डीडी-I]

अनिल कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2018

S.O. 6354(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. No. 2177 (E) dated 28.08.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five (45) days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections/suggestions has been received with regard to the proposed modifications.
3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

Para/ S.N.	MPD-2021	
	Existing Provision in MPD-2021	Proposed Amendments/Modifications
CHAPTER-7.0 INDUSTRY		
1	7.4 HOUSEHOLD / SERVICE INDUSTRIES	
	ii) The industrial units could be permitted only after provisional registration by the Govt. of NCTD.	Sub-para (ii) to be deleted; and sub-paras (iii) to (vi) to be renumbered as (ii) to (v).
2	7.8 INDUSTRY USE ZONE – GUIDELINES	
	i) The new industrial areas to be developed may have plotted development for individual industrial units.	i) The new industrial areas to be developed may have plotted development for individual industrial units.

[F.No. K-12011/5/2017-DD-I]

ANIL KUMAR, Under Secy.